खाते में कल आएंगे 35 हजार

पहली बार 2.15 लाख इंदिरा आवास लाभार्थी होंगे लाभान्वित

रमण शुक्ला, पटना

- पहले चरण में होगा 750 करोड़ रुपये का भुगतान
- ईएफएमएस के जरिए पहल को लागू करने की तैयारी पूरी

सूबे के 2.15 लाख इंदिरा आवास लाभार्थियों के बैंक खाते में एकमुश्त 35 हजार रुपया शुक्रवार को पहुंचेगा। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (ईएफएमएस) के जरिए भुगतान सुनिश्चित करने की कवायद पूरी कर ली है। ग्रामीण विकास विभाग ने पहल को अमलीजामा पहनाने के लिए गुरुवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस दौरान परीक्षण के तौर कुछ लाभार्थियों के खाते भुगतान करने की तैयारी है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि पहले चरण में 750 करोड़ रुपये भुगतान का आवंटन जारी कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण यह है कि अब इंदिरा आवास के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली राशि अब चेक से नहीं बल्कि सीधे खाते में जमा होगी। भारत सरकार के निर्देश पर शासन ने योजना में ईएफएमएस लागू करने की मशक्कत शुरू कर दी है। लाभार्थियों के खातों को प्रमाणित कर आवास सॉफ्ट में फ्रीज करने व डिजिटल हस्ताक्षर कर डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली से जोड़ने के लिए शासन ने अधिकारियों को अधिकृत कर दिया है।

गौरतलब है कि मनरेगा योजना में ईएफएमएस प्रणाली शुरू होने के सकारात्मक परिणाम मिलने पर भारत सरकार ने इंदिरा आवास योजना में भी इसे लागू करने का निर्णय किया है। इंदिरा आवास योजना में पारदर्शिता के लिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने कई बार समय-समय पर प्रक्रिया में कई बदलाव किए। फिर भी आवास लाभार्थियों को समय पर किस्त राशि नहीं मिलने और बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने की शिकायत मिलने लगी। तो सरकार ने इसे गंभीरता से लेकर पारदर्शिता के लिए योजना में ईएफएमएस व डीबीटी लागू करने पर जोर दिया है।

यह मिलेगा फायदा

- ईएफएमएस से योजना में पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।
- लाभार्थी को बैंक और सरकारी कार्यालयों और मुखिया के यहां चेक के लिए बार-बार चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।
- वर्तमान में कभी खाता नंबर गलत तो कभी बैंककर्मियों की उदासीनता से चेक क्लियर होने में परेशानी से छुटकारा मिलेगा।